जेट को समाधान प्रक्रिया के लिए मिले और तीन महीने

मुंबई, प्रेट्र : नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसलएटी) ने बंद पड़ी प्राइवेट विमानन कंपनी जेट एयरवेज की इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया पूरी करने की अवधि 90 दिन बढ़ा दी है। जेट एयरवेज को कर्ज देने वाले बैंकों और संस्थाओं की कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (सीओसी) ने एनसीएलटी के मुंबई बेंच से कंपनी की कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रॉसेस (सीआइआरपी) पूरी करने की समय-सीमा बढ़ाने की मांग की थी। वजह यह थी कि दक्षिण अमेरिका के सिनर्जी ग्रुप ने अपनी तैयारी पूरी करने के लिए ज्यादा वक्त मांगा था।

हम कारोबारियों के लिए जोखिम उठाना बेहद जरूरी है। भारत में संभावनाओं की कोई कमी नहीं है और इकोनॉमी मजबूत है।
– अनिल अग्रवाल
चेयरमैन, वेदांता रिसोर्सेज

संसेक्स	निफ्टी	सोना (प्रति दस ग्राम)	चांदी (प्रति किलोग्राम)	डॉलर	क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)
41,681.54 ▲ 7.62	12,271.80 ▲ 12.10	₹ 38,894 ▲ ₹109	₹ 45,786 ▲ ₹338	₹ 71.12 ▲ ₹0.09	$ 66.25

हमसे पहले इकोनॉमी की तबाही का तमाशा देख रहे थे कुछ लोग : मोदी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

एसोचैम के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के अपने प्रयासों को उद्योग जगत से साझा किया। उन्होंने कहा कि बीते पांच वर्षों में देश ने खुद को इतना मजबूत किया है कि कठिन लक्ष्य भी रखे जा सकते हैं और उन्हें प्राप्त भी किया जा सकता है। पहले लोग सिर्फ इकोनॉमी की तबाही का तमाशा देख रहे थे।

मोदी ने उद्योगों के हित में उठाए गए कदमों पर सवाल उठाने के लिए विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, 'उद्योग जगत के हित में उठाए जाने वाले हर फैसले पर सवाल उठाना ही कुछ लोगों ने अपना दायित्व समझ लिया है। जब 2014 से पहले के बरसों में अर्थव्यवस्था तबाह हो रही थी, उस समय अर्थव्यवस्था को संभालने वाले लोग किस तरह तमाशा देखते रहे, यह देश को नहीं भूलना चाहिए।'

प्रधानमंत्री ने कहा, 'आप अच्छी तरह जानते हैं कि पांच-छह साल पहले हमारी अर्थव्यवस्था डिजास्टर की तरफ बढ़ रही थी। हमारी सरकार ने न सिर्फ इसे रोका है बल्कि इकोनॉमी में डिसिप्लीन लाने का प्रयास किया है। हम भारत को फॉर्मलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के दो महत्वपूर्ण पिलर पर खड़ा कर रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाने के तमाम उपायों से लेकर जीएसटी तक, आधार लिंक्ड पेमेंट से लेकर डीबीटी तक अर्थव्यवस्था के ज्यादातर आयामों को फॉर्मल व्यवस्था में लाने का प्रयास किया। इसके साथ ही हम अर्थव्यवस्था को आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मॉडर्नाइज और स्पीड अप करने की दिशा में भी आगे बढ़े हैं।' उन्होंने बीते पांच वर्षों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में सरकार के कामों का भी जिक्र किया जिनके चलते भारत 190 देशों की सूची में 142वें स्थान से आज 63वें स्थान पर आ गया है। मोदी ने कहा कि सरकार ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के जरिये कंपनियों को बेहतर एक्जिट रूट दिया।

उद्योग जगत से देश की अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ाने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'संकल्प से सिद्धि के इसी सकारात्मक और पारदर्शी माहौल में आपके लिए भी अवसरों का विस्तार हो रहा है। आपका हौसला पहले से बेहतर हो, वेल्थ क्रिएशन और जॉब क्रिएशन भी पहले से बेहतर हो, इसके लिए सरकार हर तरह से उद्योग जगत के साथ खड़ी है। पूरी दुनिया का बाजार हमारे सामने है। पूरी दुनिया को टक्कर देने का साहस हमारे भीतर है। आपका संकल्प और आपका सामर्थ्य पांच ट्रिलियन डॉलर के भारत के सपने को पूरा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है।'

उन्होंने कहा कि सरकार ने कंपनी एक्ट में छोटी गलतियों के लिए आपराधिक कार्रवाई करने वाले प्रावधानों को खत्म कर उद्योगों को राहत दी। अब भी यह प्रक्रिया जारी है। इस साल से टैक्सपेयर और आयकर विभाग के बीच ह्यूमन इंटरफेस को खत्म किया है। अब देश फेसलेस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने श्रम सुधारों की दिशा में उठाए गए साहसिक कदमों का भी ब्योरा दिया।

बोले मोदी

- अर्थव्यवस्था को फॉर्मलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के पिलर पर खड़ा करने की कोशिश
- संकल्प से सिद्धि के इस माहौल में उद्योग जगत के लिए भी पैदा हो रहे विकास के अवसर

उद्योग संगठन एसोचैम के सालाना समारोह में पोस्टल टिकट जारी करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व संगठन के अधिकारीगण। प्रेट्र

उद्योगों को इकोनॉमी के प्रति शंकाओं से निकलना होगा : वित्त मंत्री

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- वित्त मंत्री ने इंडस्ट्री से किया निवेश का आग्रह
- कहा – सुधार के उपायों का दिखने लगा असर

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत से कहा है कि उसे इकोनॉमी को लेकर अपने संदेहों के घेरे से निकलना होगा। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के बजट और उसके बाद जो निर्णय किए, उनके असर दिखने शुरू हो गए हैं। वित्त मंत्री ने छोटे और मझोले उद्योगों से भी कहा वे अपनी कर्ज संबंधी दिक्कतों को लेकर किसी भी सरकारी बैंक की मदद ले सकते हैं।

उद्योग संगठन एसोचैम की सालाना बैठक में उद्योगपतियों के साथ एक परिचर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सिस्टम बदलने को लेकर प्रतिबद्ध है। कुछ कड़े निर्णय किए हैं और यह सुनिश्चित किया है कि ये उद्योग के अनुकूल हों। पिछले पांच वर्ष में सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों ने भारत को पूरी दुनिया में नई पहचान दी है। इंडस्ट्री भी इस बदलाव का हिस्सा बनी है।

सीतारमण ने इंडस्ट्री को 'हो पाएगा या नहीं' वाली शंका की स्थिति से बाहर आने को कहा है। उन्होंने कहा कि नकारात्मकता वाले इस मूड के साथ काम नहीं करना चाहिए। इससे बाहर निकलिए। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के ज्यादातर संकेतक, खासतौर पर माइक्रो इकोनॉमी के इंडिकेटर मजबूत हो रहे हैं। महंगाई की दर नियंत्रण में है, एफडीआइ का प्रवाह मजबूत बना हुआ है। विदेशी मुद्रा के भंडार रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। सरकारी बैंकों में भी पेशेवर तरीके से काम होने लगा है।

इंडस्ट्री से भारत की ग्रोथ स्टोरी में शामिल होने को आह्वान करते हुए सीतारमण ने कहा कि वह विनिवेश में हिस्सा ले और सरकारी कंपनियों के लिए बोली लगाए। सरकार नहीं चाहती कि कोई भी कारोबार बंद हो। सरकार कानूनी और प्रशासनिक बदलावों के जरिये उन्हें फिर से शुरू करने के प्रयास कर रही है। वित्त मंत्री ने इंडस्ट्री को भरोसा दिया कि सरकार उनके साथ है। नकदी की समस्या को दूर करने के साथ-साथ बैंकों को पेशेवर बनाने, गैर-बैंकिंग कंपनियों को मदद करने, रियल एस्टेट से जुड़ी समस्याओं के खात्मे और एमएसएमई के लिए कर्ज की दिक्कत को दूर करने जैसे कई कदम गिनाए, जिन्हें सरकार ने पिछले छह महीने में उठाया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स कलेक्शन में पारदर्शिता के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया है ताकि उद्योगों और करदाताओं को परेशानी से बचाया जा सके।

फैसला ▶ आनंद महिंद्रा छोड़ेंगे कार्यकारी चेयरमैन पद, बने रहेंगे कंपनी के निदेशक बोर्ड में

बड़े बदलाव की ओर महिंद्रा ग्रुप

सीईओ के नए सृजित पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी एमडी पवन गोयनका को

नई दिल्ली, प्रेट्र : महिंद्रा ग्रुप ने अपने शीर्ष प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि आनंद महिंद्रा एक्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से इस्तीफा देंगे। वे अगले वर्ष अप्रैल से नॉन-एक्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में कंपनी के निदेशक बोर्ड का हिस्सा बने रहेंगे। कंपनी ने एमडी के पद पर पवन कुमार गोयनका की दोबारा नियुक्ति की है और उन्हें सीईओ के नव-सृजित पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।

ग्रुप द्वारा किए बदलाव की घोषणा पर आनंद महिंद्रा ने कहा कि इस योजना से कंपनी के प्रबंधन में टैलेंट की गहराई की झलक मिलती है। उन्होंने कहा कि कंपनी अपनी संस्कृति, मूल्यों, प्रशासन और प्रभावी कामकाज के मामले में बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि नई भूमिका में वे कंपनी के मूल्यों और शेयरधारकों के हितों की रखवाली करते रहेंगे। महिंद्रा ने कहा कि वे कंपनी के इंटरनल ऑडिट पर नजर बनाए रहेंगे। इसके साथ ही वे कंपनी बोर्ड के माध्यम से भी प्रशासनिक कामकाज की देखरेख करेंगे।

आनंद महिंद्रा ने 2012 में केशुब महिंद्रा के रिटायरमेंट के बाद कंपनी के चेयरमैन का पद संभाला था। महिंद्रा ग्रुप सॉफ्टवेयर से लेकर एयरोस्पेस तक के कारोबार में सक्रिय है। आनंद महिंद्रा के कार्यकाल में ग्रुप ने घरेलू और विदेशी दोनों मोर्चों पर उल्लेखनीय प्रगति की है। इस दौरान कंपनी ने सैंगयोंग मोटर्स, रेवा इलेक्ट्रिक कार कंपनी, सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेस, प्यूगो मोटरसाइकिल्स जैसे सफल अधिग्रहणों को अंजाम दिया।

आनंद महिंद्रा फाइल फोटो

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर फोकस

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर फोकस करते हुए कंपनी ने सीईओ का नया पद सृजित किया है। निकट भविष्य में फोर्ड इंडिया के साथ मिलकर कंपनी इस क्षेत्र में विस्तार की योजना बना रही है। कंपनी की महिंद्रा लॉजिस्टिक्स और ऑटो मोबिलिटी सर्विसेस को मिलाकर मोबिलिटी सर्विस सेक्टर स्थापित करने की योजना है।

ग्रुप में ऐसे बढ़ा गोयनका का पद

गोयनका वर्ष 1993 में जनरल मैनेजर के रूप में कंपनी से जुड़े थे। उन्होंने अमेरिका के डेट्रॉएट स्थित रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में अपना कामकाज संभाला था। गौरतलब है कि कंपनी के सफल एसयूवी ब्रांड स्कॉर्पियो के विकास में गोयनका की प्रमुख भूमिका रही है।

ऐसे परवान चढ़ेगा बदलाव

- अप्रैल 2021 में गोयनका की सेवानिवृत्ति के बाद अनीश शाह कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ होंगे
- शाह महिंद्रा एंड महिंद्रा के बोर्ड से डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीएफओ के रूप में जुड़ेंगे
- वर्तमान सीएफओ वीएस पार्थसारथी नवगठित मोबिलिटी सर्विस सेक्टर की कमान संभालेंगे

महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में गिरावट

नई दिल्ली, प्रेट्र : शुक्रवार को प्रबंधन में फेरबदल की खबरों के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में करीब एक परसेंट की गिरावट दर्ज की गई। बीएसई में कंपनी के शेयर 0.79 परसेंट की गिरावट के साथ 530.80 रुपये पर बंद हुए। इंट्रा-डे में यह 1.25 परसेंट तक लुढ़क गए थे। वहीं एनएसई में भी कंपनी के शेयरों को 0.85 परसेंट गिरावट का सामना करना पड़ा।

सवा पांच लाख करोड़ रुपये मूल्य के स्पेक्ट्रम की होगी नीलामी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : दूरसंचार विभाग से जुड़े डिजिटल कम्यूनिकेशन कमीशन (डीसीसी) ने 5.23 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 8,300 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दे दी है। यह नीलामी मार्च-अप्रैल में होने की संभावना है।

दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश ने बताया कि डीसीसी ने दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की सिफारिश को मंजूर कर लिया है। हमें उम्मीद है कि मार्च-अप्रैल में स्पेक्ट्रम की नीलामी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 22 टेलीकॉम सर्किल में 8,305.75 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी का रिजर्व प्राइस 5,22,850 करोड़ रुपये बनता है।

ट्राई ने शुरू में 4.9 लाख करोड़ रुपये रिजर्व प्राइस की सिफारिश की थी। परंतु बाद में दूरसंचार विभाग ने रिलायंस कम्यूनिकेशंस तथा भारती एयरटेल के आठ सर्किल में लाइसेंस अवधि समाप्त होने से हासिल स्पेक्ट्रम को भी शामिल कर लिया। इससे रिजर्व प्राइस बढ़ा। अंशु प्रकाश ने बताया कि सफल बोलीदाता कंपनियों को एक गीगाहट्र्ज (1,000 मेगाहट्र्ज) से कम फ्रीक्वेंसी बैंड वाले स्पेक्ट्रम के लिए 25 प्रतिशत, जबकि उससे ऊपर के स्पेक्ट्रम के लिए 50 प्रतिशत राशि का अग्रिम भुगतान करना होगा।

भारत का आर्थिक परिदृश्य मजबूत : फिच रेटिंग्स

नई दिल्ली, आइएएनएस : तमाम चुनौतियों के बावजूद मध्यम अवधि के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का आउटलुक समान श्रेणी के अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत के लिए लंबी अवधि की आइडीआर (फॉरेन-करेंसी इश्यूअर डिफॉल्ट रेटिंग) 'बीबीबी माइनस' बरकरार रखी है। एजेंसी का कहना है कि आर्थिक वृद्धि को लेकर भारत का परिदृश्य स्थिर बना हुआ है। मध्यम अवधि में इसका रेटिंग बैलेंस 'बीबीबी' श्रेणी के अन्य देशों के मुकाबले बहुत मजबूत है।

एजेंसी ने ऊंचे सार्वजनिक कर्ज के मुकाबले विशाल विदेशी मुद्रा भंडार को भारतीय अर्थव्यवस्था की बड़ी ताकत बताई। इसकी बदौलत सरकार वित्तीय क्षेत्र की कमजोरी और कम प्रति व्यक्ति जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) जैसी ढांचागत समस्याओं से निपटने में सक्षम होगी।

फिच ने कहा है, 'जीडीपी वृद्धि के मामले में स्पर्धी देशों के मुकाबले भारत के लिए हमारा आउटलुक अब भी मजबूत है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की माली हालत पतली होने और उपभोक्ताओं का भरोसा कमजोर पड़ने जैसे कुछ घरेलू कारणों से ऐसा हुआ है।'

फाइल फोटो

- कहा – विशाल विदेशी मुद्रा भंडार भारतीय इकोनॉमी की बड़ी ताकत
- एजेंसी ने लंबी अवधि की आइडीआर बीबीबी माइनस बरकरार रखी

विकास दर अनुमान घटाया

नई दिल्ली, प्रेट्र : फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान एक प्रतिशत घटाकर 4.6 प्रतिशत कर दिया। इससे पहले एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 5.6 प्रतिशत की गति से विकास का अनुमान लगाया था। हालांकि, एजेंसी ने यह उम्मीद भी जताई है कि धीरे-धीरे हालात सुधरेंगे और अगले वित्त वर्ष में विकास दर 5.6 और 2021-22 में 6.5 प्रतिशत पर पहुंच जाएगी।

सबसे बड़ा ऊर्जा बाजार होगा भारत : प्रधान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा बाजार बन जाएगा। अभी भारत अमेरिका व चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। दुनिया में ऊर्जा की औसत खपत 1.3 फीसद की रफ्तार से हर वर्ष बढ़ रही है लेकिन भारत में ऊर्जा की खपत 4.5 फीसद की रफ्तार से बढ़ रही है।

उद्योग चैंबर फिक्की के सालाना समारोह को संबोधित करते हुए प्रधान ने कहा कि सबसे बड़े ऊर्जा बाजार होने की वजह से भारत को ऊर्जा आपूर्ति को लेकर भी अपनी अलग नीति बनानी होगी जिसमें पारंपरिक के साथ ही गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का एक बेहतर मिश्रण होना चाहिए।

प्रधान ने कहा कि जिस हिसाब से देश में ऊर्जा की खपत बढ़ रही है उसे देखते हुए इस क्षेत्र में बहुत ही बड़ा निवेश भी करने की जरूरत होगी। खासतौर पर गैस आधारित उद्योगों में 100 अरब डॉलर का नया निवेश अगले कुछ वर्षों में होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में गैस की हिस्सेदारी धीरे धीरे काफी बढ़ रही है। सरकार की नीति भी यही है कि गैस पर हमारी निर्भरता सबसे ज्यादा हो।

केंद्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस व स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (बीच में) फिक्की की सालाना बैठक में उद्योग संगठन की नई प्रेसिडेंट डॉ. संगीता रेड्डी व निवर्तमान प्रेसिडेंट संदीप सोमानी के साथ। जागरण

सारा फोकस निजी निवेश बढ़ाने पर हो : गीता गोपीनाथ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) की मुख्य अर्थशास्त्री डॉ. गीता गोपीनाथ ने भारत के मौजूदा सुस्ती से उबरने के लिए सबसे बड़ी जरूरत यह बताई है कि हर हाल में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए। देश के प्रमुख उद्योग चैंबर फिक्की के सालाना समारोह में एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए गोपीनाथ ने माना कि पिछली तीन तिमाहियों में भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी का आंकड़ा उनके अनुमान से भी ज्यादा है। उनके मुताबिक इस दौरान जो विकास दिखा है, वह सरकार द्वारा किए जा रहे खर्च में इजाफे की वजह से हुआ है। लेकिन आगे भी सरकारी व्यय की रफ्तार बनी रह सकती है, इसको लेकर संशय है। ऐसे में विकास को गति देने के लिए निजी निवेश बढ़ाना ही उपाय है।

गोपीनाथ का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है कि आइएमएफ अगले महीने भारत की इकोनॉमी को लेकर अपनी समीक्षा रिपोर्ट जारी करेगा। इसमें चालू वित्त वर्ष और अगले दो वित्त वर्षों के लिए आर्थिक विकास दर का अनुमान भी लगाया जाएगा। आरबीआइ ने इससे पहले चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर घटकर 4.5 प्रतिशत रह जाने की बात कही है। यह लगातार छठी तिमाही है जब विकास दर घटी है। विकासशील देशों में भारत कई वर्षों तक विकास दर के मामले में पहले स्थान पर था, लेकिन अब पांचवे स्थान पर फिसल गया है। सरकार लगातार मंथन कर रही है कि विकास दर को किस तरह से पटरी पर लाया जाए।

आइएमएफ की प्रमुख अर्थशास्त्री ने यह भी कहा कि हर अर्थव्यवस्था में सुधार की जरूरत होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि नीतियों में लगातार बदलाव किए जाएं। नीतियों के स्थायित्व के बगैर निवेशक समुदाय आगे फैसला नहीं कर सकता। उनसे जब यह पूछा गया कि क्या भारत एक मैन्यूफैक्चरिंग हब बन सकता है, तो उनका जवाब था कि निर्यात को बढ़ाए बगैर यह संभव नहीं है। अभी तक नए वैश्विक माहौल में जिस तरह से नई सप्लाई चेन बन रही है उससे भारत अलग होता दिख रहा है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) की मुख्य अर्थशास्त्री डॉ. गीता गोपीनाथ की फाइल फोटो।

आइएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री के सुझाव

1. निजी निवेश का प्रोत्साहन हो प्राथमिकता
2. ग्रामीण मांग में जान फूंकने के लिए और प्रयास जरूरी
3. सुधार जारी रहें, मगर नियमों व नीतियों में हो स्थिरता

बिजनेस सेंटिमेंट्स सुधारना जरूरी

डॉ. गोपीनाथ ने कहा कि निजी निवेश बढ़ाने के लिए बिजनेस सेंटिमेंट्स को बेहतर करने की जरूरत होगी। वर्ष 2014-15 में जब यह सरकार सत्ता में आई तो बिजनेस सेंटिमेंट काफी मजबूत था। लेकिन उसके बाद से इसमें कमी आने लगी। कारोबारी जगत में उदासीनता के लिए वित्त की समस्या एक बड़ी वजह है। बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) अलग-अलग समस्याओं से जूझ रही हैं। सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसका असर दिखने में अभी वक्त लगेगा। नए दिवालिया कानून का उदाहरण देते हुए डॉ. गोपीनाथ ने कहा कि इसे ज्यादा प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

तरीका

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया वादा, सरकार करेगी बदले की कार्रवाई, विदेश व्यापार नीति की तैयारियों में निर्यात संगठनों से की गोयल ने मुलाकात

निर्यात-बाधक देशों की पहचान करें कारोबारी : गोयल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भारतीय निर्यात पर कई देशों द्वारा लगाई जा रही अड़चनों से परेशान निर्यातकों को सरकार ने पूरी मदद का भरोसा दिया है। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यातकों से ऐसे देशों की पहचान करने को कहा है, ताकि सरकार बदले की कार्रवाई कर सके। उन्होंने इंडस्ट्री को आश्वस्त किया कि सरकार इन देशों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी।

बुधवार को उद्योग संगठनों फिक्की और एसोचैम की सालाना बैठकों में हिस्सा लेते हुए गोयल ने कहा कि इन कदमों के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि भारत वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बने। उन्होंने कहा कि निर्यात की पूरी वैल्यू चेन की समस्याओं का निदान आवश्यक है। गोयल ने फिक्की के सम्मेलन में कहा, 'हमारी सरकार किसी एक कंपनी की दिक्कतों को दूर करने में विश्वास नहीं रखती। हम समस्याओं के मूल का विश्लेषण और उसके स्थायी समाधान की दिशा में काम करते हैं।' उन्होंने आगे कहा कि सभी पक्षों को सरकार को बताना होगा कि कौन सा देश शुल्क से इतर अन्य बाधाओं या विकल्पों का इस्तेमाल कर उनके निर्यात को बाधित कर रहा है। 'हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है और आवश्यकता हुई तो उन देशों के खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई की जाएगी।'

इससे पूर्व गुरुवार को विदेश व्यापार नीति की तैयारियों के सिलसिले में गोयल ने निर्यात परिषदों और संगठनों के साथ मैराथन बैठक की। पांच घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में 37 निर्यात संवर्धन परिषदों, फियो और तीन कमोडिटी बोर्ड ने हिस्सा लिया।

बैठक में सीबीआइसी की तरफ से चिन्हित 'रिस्की एक्सपोर्ट्स' का मुद्दा भी उठा। ऐसे निर्यातकों को वित्तीय संसाधन जुटाने में दिक्कत आ रही है। वाणिज्य मंत्री ने बैठक के दौरान ही विदेश व्यापार महानिदेशक के कार्यालय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया। उन्होंने सभी संगठनों व परिषदों से 31 दिसंबर तक ऐसे एक्सपोर्ट्स की लिस्ट भेजने को कहा ताकि वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत में इस मुद्दे को विस्तार से उठाया जा सके। बैठक में आसियान समेत अन्य देशों के साथ हुए एफटीए और अन्य समझौतों पर भी चर्चा हुई।

पीयूष गोयल फाइल फोटो

- गोयल पहले भी कह चुके हैं कि कारोबार के मामले में भारत अन्य देशों के साथ जैसे को तैसा वाला व्यवहार करेगा
- आरसेप को बताया चीन-भारत का मुक्त व्यापार समझौता

ईपीसी की संख्या सीमित करने का सुझाव

गोयल ने बैठक में निर्यात संवर्धन परिषदों की संख्या को तार्किक बनाने पर भी जोर दिया ताकि काम के दोहराव से बचा जा सके। वाणिज्य मंत्री ने बड़े निर्यातकों को फियो का सदस्य बनने की सलाह दी। गोयल ने सुझाव दिया कि छोटी निर्यात परिषदों को उन्हीं के क्षेत्र में काम कर रही बड़ी परिषदों में अपना विलय कर देना चाहिए।

बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी से पॉजिटिव बने रहे शेयर बाजार

मुंबई, प्रेट्र : बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में उछाल के बल पर शेयर बाजार लगातार चौथे सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए। इस दौरान एसबीआइ, आइसीआइसीआइ बैंक, यस बैंक और एचडीएफसी के शेयरों में तेजी दर्ज की गई। दिन के कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 7.62 अंकों की बढ़त के साथ 41,681.54 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि इंट्रा-डे के दौरान यह 41,809.96 तक पहुंचने में सफल रहा था। एनएसई के 50 शेयरों वाले निफ्टी में 12.10 परसेंट की तेजी आई। यह 12,271.80 के रिकॉर्ड स्तर पर स्थिर हुआ।

सेंसेक्स पैक में टाटा स्टील के शेयरों में सबसे ज्यादा 3.23 परसेंट की तेजी दर्ज की गई। एसबीआइ, यस बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, आइसीआइसीआइ बैंक और भारतीय एयरटेल के शेयरों में भी तेजी देखने को मिली। वहीं वेदांता, कोटक बैंक, टाटा मोटर्स, आइटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और सन फार्मा के शेयर लाल निशान पर बंद हुए।

- लगातार चौथे सत्र में रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स
- भारतीय शेयर बाजारों पर मेहरबान हैं विदेशी निवेशक

जानकारों के मुताबिक बजट में सुधारात्मक कदम उठाए जाने की उम्मीद के चलते सत्र की शुरुआत में बाजार की रफ्तार तेज रही। लेकिन फिच रेटिंग्स द्वारा भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान में कटौती के बाद बाजार के उत्साह में कमी आई। इसके अलावा विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय बाजारों में भरोसा बनाए रखने की वजह से भी निवेशकों का हौसला बना रहा। एशिया के अन्य बाजारों में मिलाजुला रुख देखने को मिला। शंघाई, टोक्यो के शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुए। वहीं हांगकांग और सियोल के बाजार बढ़त दर्ज करने में सफल रहे। वाल स्ट्रीट में ट्रेड-डील का उत्साह बना हुआ है।